'कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए देश में लगाया था आपातकाल'

लोकतंत्र सेनानियों ने दिखाया अदम्य साहस : मुख्यमंत्री

- 'लोकतंत्र को किया कैद, संवैधानिक मूल्यों का किया हनन'
- मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित और पुस्तिका का विमोचन किया
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. अम्बेडकर को चुनाव में टिकट ना देकर उन्हें अपमानित करने का काम किया था

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का घृणित प्रयास किया। ये दिन भारतीय इतिहास में संविधान हत्या दिवस के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि हम उस दौर की क्रूरता को याद करें, उससे सबक लें और संकल्प लें कि भारत का लोकतंत्र कभी फिर से इस तरह के दमन का शिकार नहीं हो। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कैद कर लिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, दन्तोपन्त ठैंगड़ी जैसे लोकप्रिय नेताओं को जेल में डाल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, परिवाद व भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए सत्ता की लालसा में देश हित को नुकसान पहुंचाया। ये वही पार्टी है, जिसने देश के टुकड़े भी किए थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरूद्ध निर्णय किया, तो उन्होंने 25 जून 1975 की आधी रात को देश को आपातकाल में धकेल दिया। लेकिन भारतीय जनसंघ और राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थकों ने असाधारण साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। लोकतंत्र सेनानियों ने जेल में सत्याग्रह कर आपातकाल का विरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भारत के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। संविधान के प्रति सम्मान और डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। साथ ही, बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ की स्थापना की गई। वहीं कांग्रेस ने डॉ. अम्बेडकर को चुनाव में टिकट ना देकर उन्हें अपमानित करने का काम किया। जब अम्बेडकर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने उन्हें हराया भी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ, जिसने आपातकाल के विरूद्ध संघर्ष किया, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष बन चुका है। आज हमारी पार्टी में 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। गरीब कल्याण, विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों हासिल हुई हैं, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार चार जातियों- महिला, युवा, गरीब, मजदूर के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम पं. दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रहे हैं।

समारोह में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव, विधायक बालमुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा, जयपुर भाजपा शहर अध्यक्ष अमित गोयल सहित भाजपा प्रदेश और शहर कार्यकारिणी के पदाधिकारी, लोकतंत्र सेनानी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया और पुस्तिका का विमोचन भी किया।

132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, सहरौद का संचालन शुरू

- कुंजेद, सकतपुर, सहरोद, अरदान एवं आस-पास के क्षेत्रों को मिलेगी उच्च गुणवत्ता की बिजली
- ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में लगभग 26.44 लाख यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत छीजत की कमी संभावित है

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों को वर्ष 2027 से दिन में अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देशों की पालना में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विद्युत प्रसारण निगम ने बारां में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, सहरोद का संचालन शुरू कर दिया गया है।

प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि सहरोद के आस-पास के इलाको में बिजली सप्लाई में बार-बार ट्रिपिंग आती थी तथा वोल्टेज में उतार-चढ़ाव रहता था, इसी कारण सहरोद में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। सहरोद के 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनने से कुंजेद, सकतपुर, सहरोद, अरदान एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत छीजत में कमी आयेगी, वोल्टेज में सुधार होगा एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी।

सिहाग ने बताया कि इस ग्रिड सब-स्टेशन के बनने में 22 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में लगभग 26.44 लाख यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत छीजत की कमी संभावित है जिससे लगभग 2.2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की बचत अपेक्षित है।

राजधानी जयपुर में बीते दो-तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण कालवाड़ और निवारू रोड पर जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालात इतने बदत्तर हैं कि लोगों को सड़क पर बने गड्ढों और वहां भरे पानी में बड़ी मुश्किल से सफर करना पड़ रहा है। कालवाड़ रोड पर तो हाथोज तक खोदी गई सड़क के कारण लोग आये दिन गिरकर चोटिल हो रहे है।

शेखावत ने ली गहलोत के बयान की चुटकी

- - केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बोले, दुकान का फीता तो कट गया, सामान नहीं बिका...

जयपुर/जोधपुर । केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश चल रही है।

शेखावत ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत का एक मीम शेयर करते हुए कहा कि दुकान का फीता तो कट गया, सामान नहीं बिका...।

मीम में अशोक गहलोत और राहुल गांधी को झूठ की दुकान का फीता काटते हुए दिखाया गया है।

देवनानी फ्रांस एवं जर्मनी की सात दिवसीय यात्रा से आज लौटेंगे

देवनानी का जयपुर में होगा भव्य स्वागत

- अध्ययन भ्रमण में देवनानी ने दोनों देशों के सांसदों, प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात, ऐतिहासिक धरोहरों को भी देखा

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फ्रांस एवं जर्मनी दौरे से गुरुवार को तड़के दो बजे दिल्ली हवाई अड्डे पहुँचेगे। देवनानी की यह सात दिवसीय यात्रा थी। देवनानी दिल्ली से वायुयान द्वारा प्रातः जयपुर पहुंचेंगे।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में दो देशों की संसदीय परंपराओं और पद्धितयों की अध्ययन यात्रा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा ने राजस्थान की वैश्विक पहचान को भी एक नई गरिमा और दिशा प्रदान की है ।

देवनानी ने फ्रांस और जर्मनी के विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक संस्थानों का दौरा कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संसदीय कार्यप्रणालियों और सामाजिक विकास के विविध पहलुओं का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवलोकन किया और वरिष्ठ सांसदों, नीति-निर्माताओं तथा भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। देवनानी ने प्रवासी भारतीयों के सुझावों को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया।

इस यात्रा के दौरान देवनानी ने ''इंडो-जर्मन फाउंडेशन'', ''वेदांत-गेसेलशाफ्ट'', बर्लिन मेयर ऑफिस और स्टेट असेंबली, निर्माणाधीन गणेश मंदिर सहित विभिन्न आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक धरोहरों का अवलोकन किया। जर्मनी और फ्रांस के राजदूतवास में प्रवासी भारतीयों द्वारा सम्मान समारोह और संवाद कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र एवं राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को वैश्विक मंच पर गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी आत्मीय संवाद कर उन्हें राजस्थान से जुड़ने एवं राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आव्हान किया।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की यह यात्रा न केवल एक संसदीय अध्ययन के रूप में उल्लेखनीय रही, बल्कि इसने भारत और यूरोपीय देशों के बीच लोकतांत्रिक सहयोग, सांस्कृतिक समरसता और पारस्परिक समझ को भी सुदृढ़ किया।

जब गहलोत सरकार एक वर्ष भी पूरे नहीं कर पाई थी तभी दो खेमों में बंट गई थी : राठौड़

- राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन बताया

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन और भ्रामक हैं।

राठौड़ ने कहा कि गहलोत को शायद अपने ही कार्यकाल की यादें ताजा हो रही हैं जब उनकी सरकार एक वर्ष भी पूरे नहीं कर पाई थी कि दो खेमों में बंट गई थी। तत्समय सरकार के मंत्री-विधायक 34 दिनों तक एक पांच सितारा होटल में कैद रहे। यहां तक की गहलोत जी ने अपने सहयोगियों को ''निकम्मा और नकारा'' कहकर अपमानित भी किया।

राठौड़ ने कहा कि आज जब भाजपा सरकार जनसेवा में जुटी है तब गहलोत जी सस्ती लोकप्रियता और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए निराधार आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर के विकास कार्यों का लिया जायजा

- लापरवाही पर लगाई फटकार,जलभराव की समस्या पर अधिकारियों और ठेकेदारों को तलब किया
- प्रभावी समाधान का दिया आश्वासन
- उपमुख्यमंत्री मणिपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित एक नंबर क्षेत्र पहुंचीं, जहां कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 14 नंबर के पास चल रहे निर्माण कार्य में जलभराव की समस्या बरकरार मिली, जिस पर स्थानीय नागरिकों की शिकायत सुन उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और ठेकेदार को सख्त हिदायत दी।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को कल सुबह 10 बजे पुनः मौके पर तलब किया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पुनः स्थलीय निरीक्षण करेंगी और जलभराव की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगी।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री मणिपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित एक नंबर क्षेत्र पहुंचीं, जहां कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया। स्थानीय लोगों ने भी कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

ढ़ेर के बालाजी इलाके में भी उन्होंने दौरा किया, जहां पहले बारिश में कमर तक पानी भर जाता था, लेकिन इस बार बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था के कारण पानी नहीं भर रहा। उन्होंने इसे सकारात्मक परिवर्तन बताया और अधिकारियों की सराहना की। उपमुख्यमंत्री ने कहा अभी विकास कार्य लगातार जारी हैं और जल्द सभी समस्याओं का समाधान जनता के सामने होगा।

ढ़ेर के बालाजी इलाके में जहां कभी कमर तक पानी भर जाता था और वहां पानी की निकासी होने से लोगों में खुशी के लहर है। जब उपमुख्यमंत्री को मौके पर देखा तो स्थानीय मटकी बेचने वाली एक बुद्ध महिला ने आकर उपमुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बारिश के दौरान यहां कमर तक पानी भर जाता था और फुटपाथ पर रखी हुई उनकी मटकिया बह जाती थी जिससे उनके व्यापार को नुकसान होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने भी उनके आभार का स्वागत करते हुए उन्हें गले लगा लिया।

स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय बाद इस स्तर पर समाधान और जवाबदेही देखने को मिल रही है। उपमुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए खोजे जाएंगे रोगी

- 1.65 करोड़ अति संवेदनशील जनसंख्या की होगी स्क्रीनिंग

जयपुर। राज्य सरकार ने टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 25 जून 2025 से पूरे प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 11 जुलाई 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य राज्य की अति संवेदनशील जनसंख्या में टीबी के छिपे मामलों की समय रहते पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में संचालित इस प्रदेशव्यापी स्वास्थ्य प्रयास के अंतर्गत लगभग 1.65 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह अभियान समावेशी स्वास्थ्य नीति की ओर राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जानकारी दी कि अभियान के दौरान टीबी संक्रमण की अधिक संभावना वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति, डायबिटीज के रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान व शराब का सेवन करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी, खनन व निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिक, जेलों व झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिक शामिल हैं। इन सभी संवेदनशील वर्गों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि किसी भी संभावित टीबी रोगी की प्रारंभिक स्तर पर पहचान हो सके।

राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि इस अभियान में आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर लक्षणों की पूछताछ करेंगे। यदि किसी व्यक्ति में दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, लगातार बुखार, वजन में गिरावट, या भूख न लगना जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए भेजा जाएगा। टीबी की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा।

आवासन मंडल आयुक्त तलब, पालना नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी

- वर्ष 1980 में मानसरोवर आवास योजना में आवंटित प्लॉट का कब्जा पीड़ित को सौंपने के आदेश वर्ष 2016 में होने के बावजूद भी आज तक नहीं हुई पालना
- परिवादी ने दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों आयोग ने मंडल के आयुक्त सहित अन्य अधिकारी को जमानती वारंट से तलब किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के 9 साल पुराने आदेश की पालना से जुड़े मामले में आवासन मंडल आयुक्त को 27 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि अदालती आदेश की पालना नहीं की गई तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आवासन मंडल आयुक्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 मई, 2016 को आवासन मंडल को आदेश जारी कर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ राज्य आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक मामला गया, लेकिन हाऊसिंग बोर्ड को राहत नहीं मिली।

वहीं जिला उपभोक्ता आयोग ने अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आवासन मंडल आयुक्त को जमानती वारंट जारी कर उपस्थित होने को कहा था, लेकिन आयुक्त की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। ऐसे में आयुक्त को 27 जून को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए है।

गौरतलब है कि रमेश चन्द्र गुप्ता ने जनवरी, 1980 में मानसरोवर योजना में मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए आवेदन किया था। परिवादी ने पता बदलने पर नए पते की सूचना भी आवासन मंडल को दी थी, लेकिन मंडल ने मकान का आरक्षण पत्र पुराने पते पर ही भेजा। जिससे वह तय अवधि में राशि जमा नहीं करा सका।

वहीं बाद में कई बार प्रार्थना करने पर भी उसे मकान का आवंटन नहीं किया। इस पर परिवादी ने साल 2013 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया। जिस पर 3 मई, 2016 को फैसला देते हुए आयोग ने साल 2010 की दर से दो माह में आवास आवंटित करने को कहा और साथ ही आवासन मंडल पर 1.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया।

इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग तक अपील की गई, लेकिन आवासन मंडल को राहत नहीं मिली। दूसरी ओर परिवादी ने जिला आयोग में प्रार्थना पत्र पेश कर दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों आयोग ने मंडल के आयुक्त सहित अन्य अधिकारी को जमानती वारंट से तलब किया। इस आदेश को आयुक्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

बिजली कनेक्शन देने में देरी हुई तो दोषी अफसर पर गाज गिरेगी : डिस्कॉम चेयरमैन

- कनेक्शन में विलम्ब की पुष्टि के लिए आवेदकों को लगाए अभियंताओं ने फोन

जयपुर । डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने निर्देश दिए हैं कि बिजली कनेक्शन जारी करने में देरी को प्रबंधन द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुश्री डोगरा बुधवार को विद्युत भवन में जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंताओं के साथ विद्युत आपूर्ति, डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेज, राजस्व, ट्रिपिंग आदि विषयों पर समीक्षा कर रही थीं।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों के जोनल मुख्य अभियंताओं के साथ बैठक की।

औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऐसे मामलों में देरी का कारण पूछा। अभियंताओं ने आवेदक के स्तर पर लंबित होना बताया। इस पर डिस्कॉम चेयरमैन ने पुष्टि के लिए तत्काल आवेदकों से मोबाइल फोन पर बात कर देरी का कारण पता करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए, जिनमें आवेदन के करीब तीन माह बाद भी कनेक्शन जारी नहीं हो सके थे। बैठक के बीच से ही अभियंताओं ने आवेदकों को फोन कर अब तक कनेक्शन नहीं होने का कारण पूछा। इन मामलों में डिमांड नोट जमा नहीं कराने, विदेश यात्रा पर जाने जैसे आवेदक के स्तर पर विलंब के कारण सामने आए।

डोगरा ने कहा कि घरेलू एवं अघरेलू, किसी भी प्रकार के कनेक्शन में देरी का असर डिस्कॉम की छवि पर पड़ता है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रेणियों में उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र कनेक्शन मिले।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने इस दौरान अभियंताओं को 50 हजार से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली, बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने, ट्रिपिंग रोकने के लिए ग्रिड सब स्टेशनों एवं फीडरों की नियमित चेकिंग तथा उनमें लोड के अनुरूप सुधार के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों के जोनल मुख्य अभियंताओं के साथ बैठक में निर्देश दिए कि विद्युत तंत्र में सुधार के लिए फील्ड विजिट बढ़ाएं। सुश्री डोगरा ने कहा कि प्रत्येक जोन में एफआरटी, हाई लॉस वाले सब डिवीजन, जीएसएस, सीएलआरसी पर दिए जाने वाले कार्यों तथा आरडीएसएस योजना के कार्यों की प्रगति एवं आवश्यक सुधार कार्यों का निरीक्षण करें।

विद्याधर नगर में जेडीए की कार्रवाई के दौरान विवाद

- कियोस्क हटाने को लेकर दो पक्षों में झड़प
- पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया

जयपुर। विद्याधर नगर सेक्टर 8 में जेडीए की कार्रवाई के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद कियोस्क हटाने और अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि गहलोत सरकार के दौरान जिन कियोस्क का एलॉटमेंट किया गया था, उन पर दूसरे लोगों का कब्जा है। विरोध करने वाले पक्ष ने सांकेतिक धरना दिया। उनका कहना है कि रोड पर मीट की दुकान की वजह से यहां से गुजरने वाली महिलाओं को परेशानी होती है।

वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

मोजाम्बिक में 1200 दिव्यांगों को जयपुर फुट समेत कृत्रिम उपकरण लगेंगे

जयपुर। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्द्धन सिंह ने दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की राजधानी मोपूतो में जयपुर फुट विकलांग पुर्नवास शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में 1200 द्विव्यांगों को कृत्रिम अंग जयपुर फुट तथा अन्य उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

50 दिवसीय इस विशेष शिविर का आयोजन मोजम्बिक राष्ट्र की आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर किया गया है। शिविर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के संयुक्त आयोजन में हो रहा है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने कहा कि मोजम्बिक में बड़ी संख्या में ऐसे महिला और पुरुष हैं जो 17 वर्षों तक चले मोजम्बिक के गृह युद्ध में लैण्डमाइन विस्फोट में अपने अंग गंवा चुके हैं। ऐसे ही विस्फोट की शिकर एक महिला फ्लोरेन्सिया पांच वर्ष पूर्व जयपुर आई थी और एक पैर गंवा चुकी पलोरेन्सिया को जयपुर फुट लगाकर चलने फिरने योग्य बनाया गया। फ्लोरेन्सिया और दो अन्य मोजम्बिक के तकनीशियनों को विशेष रूप से जयपुर फुट के निर्माण की विधि का प्रशिक्षण जयपुर के बी.एम.वी.एस.एस केन्द्र में दिया गया ।

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्द्धन सिंह ने मोजाम्बिक की राजधानी मोपूतो में जयपुर फुट विकलांग पुर्नवास शिविर का उद्घाटन किया।

मोपूतों में आयोजित उद्घाटन समारोह में मोजम्बिक के स्वास्थ्य मंत्री उस्सेन हिलारियो आइस्स और मोजाम्बिक स्थित भारत के उच्चायुक्त राबर्ट शेटकिनटोंग के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक उपस्थित थे । विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्द्धन सिंह ने कहा कि मोजम्बिक की आजादी के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस शिविर से जहां 1200 विकलांगों को लाभ होगा वहीं भारत और मोजम्बिक के बीच आपसी सद्भाव भी देगा । विदेश राज्य मंत्री मोजाम्बिक के स्वास्थ्य मंत्री को बी.एम.वी.एस.एस के प्रशासनिक अधिकारी विष्णुकांत शर्मा ने जयपुर फुट की निर्माण विधि की जानकारी दी यह शिविर 50 दिनों तक चलेगा ।